



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ़ 1939 (श0)
(सं0 पटना 525) पटना, वृहस्पतिवार, 22 जून 2017

सं0 2/आरोप-01-27/2014-सा0प्र0-7278
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
14 जून 2017

श्री गोपीकान्त झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 670/08, तत्कालीन उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 230 दिनांक 13.03.2014 द्वारा गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। उक्त आरोप-पत्र में निगरानी थाना कांड संख्या 51/08 दिनांक 12.08.2008 के मुख्य अभियुक्त डॉ0 राजेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बहेड़ी, दरभंगा जिन्हें दिनांक 12.08.2008 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था, को निलंबन से मुक्त करने के प्रस्ताव के साथ उनके पूर्व पदस्थापन स्थान बहेड़ी, दरभंगा में ही पुनर्पदास्थापन का प्रस्ताव दिये जाने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. प्रासंगिक मामले की समीक्षा के उपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5873 दिनांक 02.05.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 120 दिनांक 08.03.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-01 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया तथा आरोप संख्या-02 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि-निलंबन से मुक्त के बाद पूर्व के पदस्थापन स्थान पर पदस्थापन का प्रस्ताव देने में असावधानी की त्रुटि है, परंतु कदाचार का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

4. विभागीय पत्रांक 5259 दिनांक 08.04.2016 एवं 9484 दिनांक 06.07.2016 द्वारा श्री झा से प्रमाणित आरोपों के संबंध में अभ्यावेदन की मांग किये जाने पर उनके द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 13.07.2016 समर्पित किया गया।

5. श्री झा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष से असहम होते हुए असहमति के निर्धारित बिन्दुओं पर श्री झा से अभ्यावेदन की मांग किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 13101 दिनांक 26.09.2016 द्वारा अभ्यावेदन की मांग किये जाने पर श्री झा द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 13.10.2016 समर्पित किया गया।

अभ्यावेदन में श्री झा का कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 821 दिनांक 23.05.2007 में दिये गये निर्देश का प्रश्न है इसके संबंध में उनके द्वारा पूर्व के अभ्यावेदन में स्थिति स्पष्ट करते हुए उल्लेख किया गया है कि वह परिपत्र है, जो किसी नियम को अवक्रमित नहीं कर सकता है। इस परिपत्र के अनुसार कारागार

से रिहा होने के पश्चात योगदान करने पर उसे पूर्व पदस्थापित पदस्थापन स्थान पर पदस्थापन नहीं करने के संबंध में है, परन्तु इस मामले में आरोपित को कारागार से रिहा होने के पश्चात पदस्थापन नहीं किया गया था बल्कि उन्हें पुनः निलंबित कर दिया गया था। लगभग 2 वर्षों के पश्चात उनके आवेदन पर सी0सी0ए0 नियम 9(7) के अन्तर्गत विचार करते हुए, निलम्बन मुक्त करते हुए पदस्थापन का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रकार यह मामला उक्त परिपत्र के अन्तर्गत अच्छादित नहीं था। पत्र में सी0सी0ए0 रूल्स 9(7) को अंकित करते हुए कहा गया है कि नियम में यह कहीं अंकित नहीं है कि निलंबन आदेश वापस लिये जाने के पश्चात आरोपी सरकारी सेवक को पुनः उसी स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा जहाँ पर वे पूर्व में पदस्थापित थे। इसके संबंध में कहा गया है कि नियम निलंबनादेश वापस लेने पर पूर्व पदस्थापित स्थान पर पदस्थापन का उल्लेख नहीं है तो उस सरकारी सेवक को पुनः पदस्थापित स्थान पर पदस्थापित नहीं करने का भी कोई उल्लेख नहीं है। उक्त नियम के परन्तुक में निलंबनादेश वापस लेने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में उनका मानना है कि निलंबनादेश वापस लिये जाने पर वह स्वतः पूर्व पदस्थापित स्थान पर पदस्थापन का हकदार हो जाता है। उनके इसी धारणा पर आधारित प्रस्ताव को विभागीय वरीय पदाधिकारी यथा संयुक्त सचिव, अपर सचिव, प्रधान सचिव एवं विभागीय मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। यदि उनका प्रस्ताव सही नहीं था तो वरीय पदाधिकारियों को इससे सहमत नहीं होना चाहिए था। उनके द्वारा तो प्रस्ताव दिया गया था, परन्तु उसका अनुमोदन तो उच्च स्तर से हुआ था। पत्र में पूर्व पदस्थापन स्थान पर पदस्थापन का प्रस्ताव देने के कारण आरोप संख्या 01 को प्रमाणित कहा गया है। आरोप संख्या 02 के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा आरोप संख्या 03 के संबंध में कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि तीनों आरोप एक ही हैं जिसे तीन विभिन्न उप कंडिकाओं में आरोप-पत्र में अंकित किया गया है। विभागीय जाँच आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष से स्पष्ट है कि प्रपत्र 'क' में गठित आरोप निलंबन से मुक्त करने के प्रस्ताव को नियम 9(7) के अन्तर्गत बाध्यकारी मानते हुए प्रमाणित नहीं माना गया है। पूर्व पदस्थापन स्थान पर पदस्थापन का प्रस्ताव देने संबंधी आरोप को भी प्रमाणित नहीं माना गया है, बल्कि असावधानी की त्रुटि माना गया है। प्रपत्र 'क' में गठित तीसरा आरोप उपरोक्त दोनों आरोप का निष्कर्ष के रूप में अंकित है, जिसमें गंभीर कदाचार का आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में आरोप संख्या 02 के साथ ही स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए अंकित किया गया है कि "कदाचार का आरोप प्रमाणित नहीं होता है" इसलिए यह कहना कि आरोप संख्या 01 प्रमाणित होता है और आरोप संख्या 03 के संबंध में संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष अंकित नहीं है, सही नहीं है। बल्कि आरोप संख्या 01 एवं 03 को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं माना गया है, केवल आरोप संख्या 02 के संबंध में असावधानी की त्रुटि पाया गया है। जिसके संबंध में प्रसंगिक पत्रांक 5259 दिनांक 06.07.2016 के द्वारा उनसे पूर्व में ही अभ्यावेदन मांगी गई थी, जिसके संबंध में उनके द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 13.07.2016 समर्पित किया गया है। उक्त आधार पर श्री झा द्वारा विभागीय कार्यवाही को बन्द करने का अनुरोध किया गया।

6. प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं श्री झा के अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित तथ्य पाये गये :-

(i) श्री झा का यह कहना है कि सी0सी0ए0 रूल्स-9(7) के नियम में निलम्बनादेश वापस लेने पर पूर्व पदस्थापित स्थान पर पदस्थापन का उल्लेख नहीं है तथा उस सरकारी सेवक को पुनः पदस्थापित स्थान पर पदस्थापन नहीं करने का भी कोई उल्लेख नहीं है, उक्त नियम के परन्तुक में निलम्बनादेश वापस लेने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका स्पष्ट मानना है कि निलम्बनादेश वापस लिए जाने पर आरोपी पदाधिकारी स्वतः पूर्व पदस्थापित स्थान पर पदस्थापन का हकदार हो जाता है। उनके इसी धारणा पर आधारित प्रस्ताव को विभागीय वरीय पदाधिकारियों एवं विभागीय मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। यदि उनका प्रस्ताव सही नहीं था तो वरीय पदाधिकारियों को इससे सहमत नहीं होना चाहिए था। उनके द्वारा तो प्रस्ताव दिया गया था, परन्तु उसका अनुमोदन तो उच्च स्तर से हुआ था। श्री झा का यह कथन मान्य नहीं हो सकता है क्योंकि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जानेवाले मामलों में सरकारी सेवक के कारागार से छूटने पर पदस्थापन के संबंध में विभागीय पत्रांक 1821 दिनांक 23.05.2007 के द्वारा स्पष्ट निदेश दिये गये हैं। यदि सी0सी0ए0 रूल्स की कंडिका-9(7) में निलम्बनादेश वापस लेने पर पूर्व पदस्थापित स्थान पर पदस्थापित किये जाने अथवा नहीं किये जाने का उल्लेख नहीं है तो ऐसी स्थिति में श्री झा को उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के निदेशों के अनुसार प्रस्ताव दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है।

(ii) श्री झा का यह कहना है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप संख्या 02 को असावधानी की त्रुटि माना गया है। विभागीय कार्य बोझ के कारण कभी-कभार इस प्रकार की त्रुटियाँ कार्य सम्पादन के दौरान हो जाया करती है। इस संदर्भ में इनका यह भी कहना है कि आरोपी पदाधिकारी के कारागार से छूटने पर योगदान देने पर उनका योगदान स्वीकृत कर उन्हें निलम्बित किया गया था। आरोपी पदाधिकारी के दो वर्षों तक निलम्बन में रहने के पश्चात् उन्हें पूर्व पदस्थापन स्थान पर नियम-9(7) के तहत पदस्थापन का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे सभी वरीय पदाधिकारियों एवं विभागीय मंत्री के द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह भी विचारणीय है कि परिपत्र/नियमावली के नियम को अवक्रमित कर सकता है कि नहीं। श्री झा का यह कथन मान्य नहीं हो सकता है क्योंकि प्रासंगिक परिपत्र के द्वारा नियमावली को अवक्रमित नहीं किया गया है, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जानेवाले मामलों में सरकारी सेवक के कारागार से छूटने पर पदस्थापन के संबंध में स्पष्ट निदेश निर्गत किये गये हैं। प्रासंगिक पत्र के द्वारा ऐसे सरकारी सेवक के द्वारा पुनः उसी पद पर पदासीन रहने दिये जाने की स्थिति में सबूतों से छेड़-छाड़ किये जाने तथा अनुसंधान को प्रभावित करने की संभावना बने रहने के कारण उन्हें पूर्व के धारित पद, जिसपर रहते हुए, वे रिश्वत

लेते पकड़े गये हों, से तुरन्त स्थानान्तरित कर देने का निदेश निर्गत किया गया है। सरकारी परिपत्र के द्वारा स्पष्ट निदेश निर्गत रहने के बावजूद ऐसे गंभीर मामले में स्पष्ट प्रस्ताव नहीं दिये जाने के आलोक में इस बिन्दु पर श्री झा का कथन मान्य नहीं है।

(iii) श्री झा के द्वारा डॉ० सिन्हा के निलम्बनमुक्ति के बाद पूर्व पदस्थापन स्थान पर ही पुनर्पदस्थापन का प्रस्ताव दिये जाने से यह स्पष्ट है कि श्री झा के द्वारा डॉ० सिन्हा को मदद करने की नीयत से उपर्युक्त प्रस्ताव दिया गया है। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये गये आरोपी पदाधिकारी को पूर्व पदस्थापन स्थान पर ही पुनर्पदस्थापन का प्रस्ताव दिये जाने से यह स्वतः स्पष्ट है कि श्री झा के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक नहीं किया गया है एवं ऐसे आरोपी पदाधिकारी को संरक्षण देकर कदाचार किया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री झा के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए श्री झा के **पेंशन से 10% राशि की कटौती पाँच वर्षों तक** किये जाने का दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

8. उपर्युक्त विनिश्चित दंड पर विभागीय पत्रांक 16865 दिनांक 20.12.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3559 दिनांक 08.03.2017 द्वारा दंड प्रस्ताव के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दंड अधिक होने के कारण आनुपातिक नहीं है।

9. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा संसूचित अभिमत से असहमत होते हुए श्री झा के विरुद्ध **“पेंशन से 10% राशि की कटौती पाँच वर्षों तक”** किये जाने के दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

10. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के प्रावधान के तहत श्री गोपीकान्त झा (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 670/08, तत्कालीन उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के **“पेंशन से 10% राशि की कटौती पाँच वर्षों तक”** किये जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 525-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>